Topic: The Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by UN General Assembly in September 2015

The concept of the SDGs was born at the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20, in 2012. The objective was to produce a set of universally applicable goals that balances the three dimensions of sustainable development: environmental, social, and economic. The SDGs replace the Millennium Development Goals (MDGs), which in September 2000 rallied the world around a common 15-year agenda to tackle the indignity of poverty.17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by world leaders in September 2015 at a historic UN Summit — officially came into force on 1st January 2016. Over the next fifteen years, with these new goals that universally apply to all, countries will mobilize efforts to end all forms of poverty, fight inequalities and tackle climate change, ensuring that no one is left behind.

The SDGs build on the success of the Millennium Development Goals (MDGs) and aim to go further to end all forms of poverty. The new goals are unique in that they call for action by all countries, poor, rich and middle-income to promote prosperity while protecting the planet. While the SDGs are not legally binding, governments are expected to take ownership and establish national frameworks for the achievement of the seventeen goals. Countries have the primary responsibility for follow-up and review of the progress made in implementing the goals, which will require quality, accessible and timely data collection. Regional follow-up and review will be based on national-level analyses and contribute to follow-up and review at the global level.

In this context, the proposed theme of the essay may emphasise upon the niche area and may facilitate the solutions to specific issues such as; India's framework of action plan with respect to the SDGs, What would be India's strategy to achieve the global goals of action on climate change and the environment, improved access to health and education? What support should be extended to government to reflect the new global agenda in national development plans and policies? How would the challenges of financial resources meet the global development challenges? What would be the national indicators for the framed SDGs? How adequate and reliable is the existing data to frame a policy on the related issues. What are the challenges as a nation to meet the SDGs in the present context?

Essay should be original and creative in content selection and presentation. The effectiveness and clarity in communicating ideas should be an integral part of the essay.

विषय (2) : सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए सतत् विकास लक्ष्य (एस डी जीज़)

एस डी जीज की संकल्पना का उद्भव 2012 में सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन, रियो+20 में हुआ। इसका उद्देश्य था सतत विकास के तीन आयामों–पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक––को संतुलित करने के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करना। सतत विकास लक्ष्य (एस डी जीज़), सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्रतिस्थापित करते हैं––जिन्होंने सितंबर 2000 में, निर्धनता का समाधान कराने के लिए 15 वर्षीय सामान्य कार्यसूची हेतु विश्व को एकत्रित किया। सितंबर 2015 में हुए ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडा के 17 सतत विकास लक्ष्य 1 जनवरी, 2016 को अधिकारिक रूप से अस्तित्व में आए। अगले 15 वर्षों में, सभी पर सार्वजनिक रूप से लागू इन नए लक्ष्यों के साथ, सभी प्रकार की निर्धनता समाप्त करने, असमानताओं से लड़ने तथा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए सभी देश मिलकर प्रयास करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छूटे नहीं।

सतत विकास लक्ष्यों (एस डी जीज़) का निर्माण सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की सफलता पर किया गया है तथा इनका उद्देश्य है आगे सभी प्रकार की निर्धनता को समाप्त करना। ये नए लक्ष्य इस मामले में अनूठे हैं कि इनमें सभी देशों–चाहे वे निर्धन हों, समृद्ध हों अथवा मध्यम आय वाले हों––से ग्रह की रक्षा करते हुए समृद्धि प्रोन्नत करने का आवाहन किया गया है। यद्यपि सतत विकास लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, किंतु सरकारों से अपेक्षा है कि वे अपनी ओर से इन सत्रह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय ढाँचा तैयार

करें। देशों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वे इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करें, जिसके लिए गुणवत्ता, पहुँच तथा समय पर आँकड़े एकत्रित करना अपेक्षित होगा। क्षेत्रीय जाँच तथा पुनरीक्षण राष्ट्र–स्तरीय विश्लेषण पर आधारित होगा तथा यह विश्व स्तर पर जाँच तथा पुनरीक्षण में योगदान देगा।

इस संदर्भ में, निबंध को आला क्षेत्र पर बल देना चाहिए तथा इसे निम्न विशिष्ट मुद्दों का समाधान सुगम कराना चाहिए, जैसेः सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भारत की कार्ययोजना की रूपरेखा, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण पर कार्यवाही हेतु विश्व लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की रणनीति, स्वास्थ्य तथा शिक्षा तक बेहतर पहुँच। राष्ट्रीय विकास योनाओं तथा नीतियों में नवीन वैश्विक कार्यसूचनी प्रतिबिंबित करने के लिए सरकार को क्या समर्थन दिया जाना चाहिए? वित्तीय संसाधनों की चुनौतियाँ, वैश्विक विकास चुनौतियों का मुकाबला कैसे करेंगी? फ्रेम किए हुए सतत विकास लक्ष्यों हेतु राष्ट्रीय संकेतक क्या होंगे? संबंधित मुद्दों पर नीति निर्धारित करने के लिए विद्यमान आँकड़े कितने पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं? वर्तमान संदर्भ में, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राष्ट्र के रूप में हमारे सामने क्या चुनौतियॉ हैं?

निबंध की विषय–वस्तु चयन तथा प्रस्तुतीकरण मौलिक तथा सृजनात्मक होना चाहिए। विचार संप्रेषण में स्पष्टता तथा प्रभावकारिता निबंधों का एक अभिन्न अंग होना चाहिए ।